

वाडा ने दी साफाई कहा- गत मायने निकाले गए
नई दिल्ली, ईएमएस कायेस संसद प्रियंका गांधी के पाति रॉवर्ट
वाडा अपने ही बयान पर धिर गए हैं। उन्होंने कहा था कि पहलगाम
हमला यह संदेश देने की कोशिश है कि देश में मुसलमान
असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने जब रॉबर्ट वाडा पर हमला
किया तो वह सफाई देने लगे।

राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय

**जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि,
फारूक अब्दुल्ला ने गैलरी में बैठ देखी कार्यवाही, सीएम उमर भावुक हो बोले....**

लानत हो हम पर अगर आज भी...

आदिल शाह के बलिदान को सदन ने किया नमन

● जम्मू, ईएमएस

पहलगाम में आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को खोला गया। सत्र के प्रारंभ में समस्त विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरां घाटी में हुए आतंकी हमले में मरे गए समर्थन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आकास्ती की शानि के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस विशेष सत्र की कार्यवाही को नेशनल कॉम्प्रेस के संरक्षक फारूक



मलांगी में दबे लोगों की तलाश बचाव दल द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, हूठी संचालित मीडिया ने बताया कि उत्तरी यमन में राजधानी सहित कई स्थानों पर करीब 20 अतंकी हवाई हमले किए गए।

पर्यूँ सिंह के घर हुई फायरिंग

मुजफ्फरपुर, ईएमएस। बिहार के मुजफ्फरपुर परियों के हॉस्पिट इस कठूलो बुर्के हैं कि कारी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से हिचक नहीं रहे हैं। यही कारण है कि रिवायत देर रात मिठानपुरा थाना क्लीन के रामबाग यॉरी मोहल्ले में स्थित जनता दल यूनाइटेड के महानगर उपायुक्त और अधिकारी विधायक महासभा के जिलाध्यक्ष पप्पू रितें ने आवास पर अजात बदमाशों ने अंगार्धी फायरिंग कर क्षेत्र में दबाव लगाया है। कुछ आपाराधिक तरफ बालक पर सराव होकर आए और घर पर 6 से 7 रात फायरिंग कर फरार हो गए। कारिंग के समय पप्पू रितें अपने किसी रिशेदार के साथ घर लौटे ही थे।

अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग का समर्थन

नई दिल्ली, ईएमएस। पाक के रक्षा मंत्री खवाजा असिफ ने एक रुसी समाचार परेंजी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन, रूस या परिचिनी देश मिलकर एक इंटरव्यू बल टीम बनाएं, ताकि यह जांच हो सके कि भारत सरकार जो कहा है हो वह सच है या नहीं। पाकिस्तान के प्राप्तानमंत्री शहजाद अंजाम ने भी पूरी दुनिया से इसके बारे में बात की है। इस पूरे माझे में चीन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। यही स्टार्टर के अनुसार, रविवार को पाकिस्तानी दिवेश मीटिंग में इमरान इश्कां डाक तरफ के दौरान वांग यी ने निष्पक्ष जांच की शुरुआत का समर्थन किया।

अब भारत ने की डिजिटल स्ट्राइक

नई दिल्ली, ईएमएस। पाकिस्तान पर शिकंजा करने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहने पारी रोका, पिर कई समझौते तोड़ दिया। अब भारत के शिकंजा के जहर उत्तर रहे कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिक्रिया लगाकर डिजिटल स्ट्राइक की है। सुत्रों के मुताबिक यह मात्रालय की है। प्रियंका ने एक रुसी में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस बढ़ना में उत्तर प्रदेश के अंदोच्चा में एक अवृत्ति और फतेहपुर में एक किसान की जान चली गई। वहीं, बिहार के पटना और हाजीपुर में एक-एक अवृत्ति की मौत हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए करमों का पूरी तरह से समर्थन करता है। 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में निर्वाचनों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर यह सदन गहरा दुर्ख व्यक्त करता है। इस जन्मन्य और कायराना हमले की साफ तौर पर निर्वाचन करता है। इस तरह के आतंकी हमले के चरित्र, हमरे सांविधान में निहित मूल्यों तथा एकता, शांति और सम्भवत की भावना पर सीधी हालत है, जो लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के अपराधी और हमारे देश के विशेषता रही है। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र समकार द्वारा उत्तर राज्य गए सभी करमों का हमले समर्थन करता है। उन सभी लोगों के प्रति हम गहरी गहरी संवेदन व्यक्त करते हैं जिन्हें अपर्याप्य धनि हुई है। हम उनके दुख को साझा करने और उनकी जस्तर की धड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक सकलत्य की पुष्टि करते हैं। इसके आगे प्रस्ताव में कहा गया, कि % यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद कें

जिन्होने निर्देशों का खून बहाया, उन्हें पानी नहीं मिलेगा: शिवराज
भोपाल, ईएमएस। पहले ग्राम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। अब परिक्रतान को सिंधु नदी का पानी नहीं मिल पाया। केवल सरकार के इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के अधिकारी चौधरी नवेंट कैटेक्ट ने सवाल उठाया। तो केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह हौलने जवाब दिया।

राजनीतिक प्रशासनिक

मोहन यादव सरकार का फार्मूला तैयार

4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन

► इस साल मिलेगा एक प्रमोशन का लाभ

भोपाल, ईएमएस।

मप्र में कर्मचारी-अधिकारियों की पदोन्नति का ग्रास जल्द ही खुलने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी-अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसका मसौदा तैयार करके जल्द ही इसे विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ तो मिलेगा, लेकिन वेतन बढ़ातरी का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यह पहले से ही उच्च पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 10 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, उन्हें पदोन्नति के साथ वेतन बढ़ातरी का भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है।

बताया जा रहा है कि प्रोमोशन का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। हालांकि अधिकारियों द्वारा 4 बार प्रमोशन से जुड़ा ड्राफ्ट भेजा जा चुका है, लेकिन कमेटी इसे वापस कर चुकी है। कमेटी ने एक बार फिर इसमें कई संशोधन के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि इस साल कर्मचारियों को सिपाही एक ही प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि साल में एक ही डीपीसी होती है और 2016 के बाद से भी कर्मचारी क्रमागति और इकीमेट का लाभ ले चुके हैं। जल्द ही प्रमोशन के ड्राफ्ट को कमेटी मंजूरी देकर विधि विभाग को भेजेगी। विधि विभाग की हरी झंडी के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।



अजाक्स-सपाक्स अपनी मांगों पर अड़े

उधर सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अजाक्स और सपाक्स अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर अड़े हैं। अजाक्स और उससे जुड़े अधिकारी कर्मचारी जहां 2002 के पदोन्नति के नियमों के तहत पदोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय अजाक्स राखा के अध्यक्ष घनश्याम दास भर्कीरणी का कहना है कि हमने शासन के सामने अपना पन्थ रख दिया है। इसमें कहा गया है कि 2002 के नियमों को आधार बनाकर ही पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए, या फिर सपाक्स की नियमों को पदोन्नति का आधार बनाया जाए। उधर सपाक्स के प्रेशर अध्यक्ष डॉ. केएस तोपर के मुताबिक एम नायर जन मामले से जुड़े फैसले में 2002 के नियमों के तहत पूर्व में दी गई पदोन्नति को सरकार रिवर्ट करे इसलिए इस नियमों के तहत पूर्व में दी गई पदोन्नति को सरकार रिवर्ट करे और क्रीमीलयर व्यवस्था को लागू किया जाए।

एनओटीटीओ की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार

ब्रेनडेड के बाद अंगदान में मप्र सातवें स्थान पर

भोपाल, ईएमएस। मप्र में अंगदान और देहदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए आगे भी आ रहे हैं। लेकिन यूरोपीय देशों के मुकाबले अपनी भी भारत में बहुत ही कम लागू ही कैडेवर डोनेशन के लिए सहभात हो रहे हैं। इस मामले में भोपाल सहित मप्र बहुत ही पीछे है।

एनओटीटीओ की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में देश भर में ब्रेन डेड मरीजों से 1099 कैडेवर डोनेशन मिले। इनमें से सबसे ज्यादा 252 तेलांगाना में हुए। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर कन्नटक रहा। मप्र का स्थान महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली एनसीआर के बाद भी रहा। मप्र में सिर्फ आठ कैडेवर डोनेशन के बाद साथी एवं ग्रेड ड्रेसेन के बाद सबसे लाख पर रहा। केंद्र सरकार ने लोगों को उत्तम कित्तिका उपलब्ध कराने के लिए वाले चरेल, कृषि, 5 किलोवाट तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को गहरा मिलेगा। यह छूट उन प्रकरणों के बाद अंग दान (कैडेवर डोनेशन) के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कुछ लोग

लोक अदालत में विजली प्रकरणों में मिलेगी अधिभार में छूट

10 मई को जिला और तहसील न्यायालयों में लगेगी नेशनल लोक अदालत

भोपाल, ईएमएस।

भोपाल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आगामी 10 मई को प्रदेश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बार लोक अदालत में विजिती अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में उपभोक्ताओं को बड़ी छूट मिलने जा रही है। लोक अदालत में सभी न्यायालयों करने वाले चरेल, कृषि, 5 किलोवाट तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को गहरा मिलेगा। यह छूट उन प्रकरणों पर लागू होगी, जो न्यायालय में लाभित होता जिन पर प्री-लिटिशन स्टर पर कार्रवाई होती है।

दो स्तरों पर मिलेगी छूट

लोक अदालत में विजिती प्रकरणों में दो स्तरों पर छूट मिलेगी। इहां प्री-लिटिशन स्टर पर। इसके तहत कंपनी द्वारा आंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी दी जाएगी। ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी की उत्तम कित्तिका उपलब्ध कराने के लिए हालांकि मैं आंकितित दिविल स्टर पर प्रदेश के कंपनी द्वारा आंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 20 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी 30 दिन की तय समय सीमा के बाद भी दी जाएगी। ब्याज की गणना 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छ. माही चक्रवृद्धि दर से होती है, लेकिन लोक अदालत में समझौता करने पर यह पूरा माफ किया जाएगा।

बजट में प्रावधान, लेकिन केन्द्र ने नहीं दी राशि

भोपाल, ईएमएस।

भले ही प्रदेश और केन्द्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन अधिक मंचों पर प्रदेश को इसका फायदा पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। हालत यह है कि बीते माह समास हुए वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार के हिस्से की पूरी राशि नहीं दी, लिहाजा प्रदेश के खजाने को 16155 को घाटा उठाना पड़ा है। दरअसल, प्रदेश सरकार को केन्द्र से 31 मार्च तक के 37652 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन उसे महज 21497 हजार करोड़ रुपये ही मिल सके हैं।

इस तरह से 16155 करोड़ रुपये कम दिए गए हैं। इसके अलावा कई विभागों ने भी राशि दिया है। यह विधिक विभागों की बात करें तो उनमें कैलाश विजयराय, प्रह्लाद पटेल, राजेंद्र शुक्ल, उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह, संपत्ति विभाग के बाबत जिनके नाम से ज्यादा राशि की जाएगी।



शामिल हैं। अहम बात तो यह है कि केन्द्र प्रदेश के कोटि से मंत्री और प्रदेश के कोटि से नियमित विभागों ने भी राशि दिया है। इसी तरह से भी एक बड़ी राशि दिया जाएगी। जीवन विभाग की बातें तो उनमें कैलाश विजयराय, प्रह्लाद पटेल, राजेंद्र शुक्ल, उदय प्रताप सिंह, राकेश सिंह, संपत्ति विभाग के बाबत जिनके नाम से ज्यादा राशि की जाएगी।

सीएम डैशबोर्ड से विभागों की निगरानी होगी आसान

कलेक्टरों की परफॉर्मेंस का मिलेगा लाइव अपडेट

भोपाल, ईएमएस। मप्र में अब सरकारी योजनाओं की क्रियावाही प्रकरणों में दो स्तरों पर छूट मिलेगी। इहां प्री-लिटिशन स्टर पर। इसके तहत कंपनी द्वारा आंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी दी जाएगी। ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी 30 दिन की तय समय सीमा के बाद भी दी जाएगी। ब्याज की गणना 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छ. माही चक्रवृद्धि दर से होती है, लेकिन लोक अदालत में समझौता करने पर यह पूरा माफ किया जाएगा।

नगरीय आवास और विकास विभागों को भी आंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। ब्याज पर 100 प्रतिशत मार्फी 30 दिन की तय समय सीमा के बाद भी दी जाएगी। ब्याज की गणना 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छ. माही चक्रवृद्धि दर से होती है, लेकिन लोक अदालत में समझौता करने पर यह पूरा माफ किया जाएगा।

नगरीय आवास और विकास विभागों की क्रियावाही को भी 1400 करोड़ रुपये कमिला है। इसके तहत अनुग्रह 2.0 के लिए 51.03 करोड़ शहरी स्वरूप भारत में 2.0 कैपिटलीटी विडिङ्गों के लिए 22.64 करोड़ रुपये, जबलपुर और उजौजै स्टर्ट रिटार्न के लिए अलग-अलग 14-14 करोड़ रुपये में दो रेटों पर। इसके तहत कलेक्टरों के प्रत्येक दिविल दिवित्य राशि पर 20 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। इसी तरह से भी एक बड़ा अंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 20 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। इसी तरह से भी एक बड़ा अंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 20 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। इसी तरह से भी एक बड़ा अंकितित दिविल दिवित्य राशि पर 20 प्रतिशत मार्फी की छूट दी जाएगी। इसी तरह